

संपादकीय

आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, हथियार नहीं

देश और दुनिया में इन दिनों युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नारों में सत्ता बदलने की मांग है और सोशल मीडिया पर घटनाएं तेजी से फैल रही हैं। नेपाल से लेकर फ्रांस और बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक आंदोलनों ने सत्ताओं को चुनौती दी है। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का संदेश महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में आंदोलन स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें समाधान का मार्ग बनना चाहिए, द्वेष और सत्ता हथियाने का औजार नहीं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक एकता के लिए जरूरी चेतावनी है।

आज युवाओं और आंदोलनों का प्रभाव सीमाओं से परे पहुंचता है। एक देश में अपनाए गए तरीके दूसरे देशों में भी दोहराए जाते हैं, जबकि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। केवल सत्ता बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। वास्तविक बदलाव के लिए निरंतर संवाद, सुधार और जनभागीदारी आवश्यक हैं। भारत के लोकतंत्र की अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए समस्याओं के समाधान भी देश की परिस्थितियों के अनुरूप खोजने होंगे।

लोकतंत्र में आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब संसद में जनता की आवाज नहीं सुनी जाती और प्रशासन समस्याओं की अनदेखी करता है, तब लोग सड़कों पर उतरते हैं। यही जनभागीदारी लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन आंदोलन की सार्थकता तभी है, जब उसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान हो। यदि वह केवल विरोधियों को शत्रु साबित करने या सरकार गिराने का माध्यम बन जाए, तो सामाजिक विभाजन और द्वेष बढ़ने का खतरा रहता है। आंदोलन समाज को जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। आज युवाओं का आक्रोश बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, आवास की बढ़ती लागत और भविष्य की अनिश्चितता जैसे वास्तविक कारणों से जुड़ा है। उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस आक्रोश को भड़काना उचित नहीं है। युवाओं को किसी सत्ता संघर्ष का मोहरा बनाने के बजाय उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देना जरूरी है। यह धारणा भी गलत है कि हर समस्या का समाधान सत्ता परिवर्तन में छिपा है। इतिहास बताता है कि सरकारें बदलने के बाद भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। इसलिए आंदोलनों का उद्देश्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना और सुधारों के लिए दबाव पैदा करना होना चाहिए।

डिजिटल युग में आंदोलनों का स्वरूप तेजी से बदला है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनआक्रोश कुछ ही घंटों में व्यापक रूप ले सकता है। ऐसे में भ्रामक सूचनाओं और राजनीतिक दुष्प्रचार से सावधान रहना जरूरी है। युवाओं में विवेकपूर्ण सोच विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। सत्ता पक्ष को जनता की शिकायतें सुननी चाहिए और विपक्ष को रचनात्मक विरोध की भूमिका निभानी चाहिए। आंदोलन को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेना लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करता है। लोकतंत्र में सत्ता का निर्णय चुनाव के माध्यम से जनता करती है। शांतिपूर्ण विरोध और जनआंदोलन भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन हिंसा और दमाल के जरिए सत्ता हासिल करने को कोशिश व्यवस्था को कमजोर करती है।

आंदोलन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी जीवंतता का प्रमाण हैं। जरूरत ऐसे आंदोलनों की है, जो शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाएं। आंदोलन का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, जनहित में बदलाव लाना होना चाहिए। जब विरोध संवाद का माध्यम बनेगा और आक्रोश समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और समाज की एकता कायम रहेगी।

आजकल

कम वर्षा का संकट केवल आंकड़ा नहीं, व्यवस्था की परीक्षा

मध्यप्रदेश के आठ से अधिक जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, पाण्डुरंग, छिंदवाड़ा, हराद और शाजपुर जैसे जिले इस सूची में हैं। कम बारिश केवल मौसमी घटना नहीं, बल्कि खेतों से लेकर घरों के नलों तक असर डालने वाले संकट की शुरुआत है। इसका अर्थ है कि जमीन में कम पानी पहुंचा, बांधों में जलभराव कम हुआ और किसानों को योजनाएं प्रभावित हुईं।

रबी की बुवाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी जरूरी है। नमी की कमी से किसानों को बुवाई से पहले ही सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे लागत बढ़ती है। ऐसे में किसानों की सिंचाई के लिए पानी की मांग स्वाभाविक है, लेकिन प्रशासन को इसे सामान्य प्रक्रिया के बजाय असाामान्य परिस्थिति मानकर देkhना चाहिए।

कम बारिश से बांधों के जल प्रबंधन का संतुलन भी बिगड़ता है। सिंचाई के लिए अधिक पानी छोड़ने पर मार्च-अप्रैल में पेयजल संकट गहरा सकता है, जबकि पानी रोकने से गेहूं, चना और सरसों की फसलें प्रभावित होंगी। इसके बावजूद कई जिलों में बांधों से पानी छोड़ने संबंधी कार्ययोजना स्पष्ट नहीं होना चिंता का विषय है। नहरों से पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर किसान ट्रब्लूवेल और बोरेवेल पर निर्भर होंगे, जिससे भूजल स्तर गिरने का खतरा बढ़ता है। अतिरिक्त सिंचाई, डीजल और बिजली का खर्च किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ाता है। समय पर पानी नहीं मिलने से बुवाई पिछड़ सकती है और पैदावार प्रभावित हो सकती है। इस संकट से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में बांधवार जल बजट तैयार कर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पेयजल और सिंचाई के बीच स्पष्ट प्राथमिकता तय करने के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के प्रति किसानों की जागरूक करना भी आवश्यक है। कम बारिश प्राकृतिक परिस्थिति है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। समय रहते ठोस योजना नहीं बनी तो खेतों के साथ जलापूर्ति और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर भी संकट गहरा सकता है।

यूरोप, जिसे लंबे समय तक शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है, आज उसी की सड़कों पर आग दिखाई दे रहा है। फ्रांस के कई शहरों में हिंसा के बीच उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पेरिस में रोलेक्स, लुई विटॉन और डिजायर जैसी बड़ी कंपनियों के शोरूमों में तोड़फोड़ और लूटपाट का गई है। इटली, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम और अल्बानिया भी विरोध प्रदर्शनों से अछूते नहीं हैं। फ्रांस में पेरिस समेत कई शहरों में जारी हिंसा के दौरान सैकड़ों प्रदर्शन हुए हैं। पुलिसकर्मियों चालल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

यह दृश्य केवल एक देश का नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। सवाल उठता है कि जिस यूरोप को युवा पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य देने वाला

माना जाता था, वहां युवा ही हिंसा पर क्यों उतर आए हैं?

हर देश में विरोध के मुद्दे अलग-अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे का दर्द एक जैसा है। फ्रांस में शिक्षा का दर्द एक जैसा है। फ्रांस में शिक्षा सुधार, सार्वजनिक सेवाओं और असमानता को लेकर विरोध हुआ है। रोमानिया में महिलाओं ने शिक्षा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किए। इटली में महंगाई, स्थिर वेतन और जीवनयापन की बढ़ती लागत के खिलाफ गुस्सा है। स्पेन में घरों के किराये में कमी की मांग हो रही है। बेल्जियम में शिक्षा की बढ़ती लागत और सुधारों को लेकर असंतोष है। अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गए हैं। पुर्तगाल में आवास की बढ़ती कीमतों और जीवनयापन की कठिनाइयों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इन सभी मामों में एक समानता है, वह है भविष्य को

नईदुनिया

राष्ट्रीय स्तर पर सोने की शुद्धता से खिलवाड़ का खेल

सोना भारतीय समाज में केवल एक धातु नहीं है। वह बचत है, सुरक्षा है, परंपरा है और भविष्य का भरोसा है। हर परिवार अपने जीवनभर की कमाई का एक हिस्सा सोने में लगाता है, ताकि बुरे समय में वही सोना काम आए। इसीलिए जब सोना खरीदा जाता है, तो ग्राहक सबसे अधिक जिस चीज पर भरोसा करता है, वह है हॉलमार्क।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हॉलमार्किंग की व्यवस्था इसीलिए बनाई थी, ताकि ग्राहक को शुद्धता की गारंटी मिल सके। लेकिन पिछले कुछ समय से देश के कई बड़े सरफा बाजारों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जो इस भरोसे को हिला रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुराने हॉलमार्क के नाम पर कथित फर्जी हॉलमार्किंग का खेल चल रहा है और सोने की शुद्धता से खिलवाड़ किया जा रहा है।

व्यवसाय से जुड़े स्रोतों का दावा है कि कुछ कारोबारी पुराने और सैंदिग्ध हॉलमार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर बिना उचित जांच के हॉलमार्क लगाए जा रहे हैं और कुछ मामलों में हॉलमार्क के निशान ही नकली लगाए जाने के आरोप हैं। नई व्यवस्था के तहत छह अंकों वाली एचयूआईडी आधारित हॉलमार्किंग लागू की गई है, ताकि हर आभूषण की पहचान और उसके विवरण का पता लगाया जा सके। इसके बावजूद आरोप हैं कि कई जगह पुराने हॉलमार्क या बिना एचयूआईडी वाले आभूषण बेचे जा रहे हैं। इससे ग्राहक के लिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि उसने जो सोना खरीदा है, वह वास्तव में कितना शुद्ध है।

ग्राहक को सोने की परख नहीं होती। वह ज्वेलर की बात और हॉलमार्क के निशान पर ही भरोसा करता है। यदि वही निशान फर्जी हो, तो ग्राहक के साथ सीधा विश्वासघात होता है। कल्पना कीजिए कि किसी परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए जीवनभर की बचत से सोने के आभूषण खरीदे और बाद में पता चले

देश में पहली बार सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड से फंडिंग, क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज

देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने एक नया प्रयोग किया है, जिसे अपनी तरह की पहली पहल बताया जा रहा है। सरकारी भागीदारी के साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से राशि जुटाने की यह पहल है। सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से चार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस राशि का उपयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जापान और जर्मनी में रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम पर किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य केवल धन जुटाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें सरकार के साथ निजी निवेशक भी सामाजिक बदलाव में भागीदार बनें और उसके परिणाम धरातल पर दिखाई दें।

मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए जापानी तथा जर्मन भाषा और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना की खस बात यह है कि संबंधित एजेंसी को भुगतान उम्मीदवारों के विदेश में प्लेसमेंट की लिखित पुष्टि मिलने के बाद ही किया जाएगा। यानी सरकारी भुगतान को केवल प्रशिक्षण देने के बजाय रोजगार से जोड़ा गया है। यह अब तक की पारंपरिक योजनाओं से अलग दृष्टिकोण है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि प्रशिक्षण केवल खानापूर्ति बनकर न रह जाए, बल्कि उसका परिणाम रोजगार के रूप में सामने आए और युवा विदेश में नौकरी पाने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

योजना के तहत मध्यप्रदेश में स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को उनकी जरूरत और निर्धारित रोजगार लक्ष्यों के अनुरूप कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ जापानी तथा जर्मन भाषा का प्रशिक्षण भी कार्यक्रम का हिस्सा होगा। एजेंसी की जिम्मेदारी केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे उम्मीदवारों को संबंधित देशों में रोजगार के लिए तैयार करने, प्लेसमेंट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कराने और विदेश में नौकरी दिलाने की प्रक्रिया में सहायता करनी होगी। यह पूरी प्रक्रिया परिणाम आधारित होगी, जिसमें एजेंसी को तभी भुगतान मिलेगा, जब वह निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेगी।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक ऐसा वित्तीय साधन है, जिसके माध्यम से सामाजिक परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाया जाता है। इसमें निवेशकों का प्रतिफल परियोजना के निर्धारित सामाजिक परिणामों से जुड़ा हो सकता है। मध्यप्रदेश में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के क्रियान्वयन से संबंधित संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। प्रदेश में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को विदेशी रोजगार के लिए जरूरी तकनीकी कौशल, भाषा प्रशिक्षण और व्यक्तित्व

नईदुनिया

राष्ट्रीय स्तर पर सोने की शुद्धता से खिलवाड़ का खेल

बीआईएस हॉलमार्क और भरोसे पर उठते सवाल



कि उनमें शुद्धता उतनी नहीं है, जितनी बताई गई थी। उस परिवार पर क्या बीतेगी? यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भावनात्मक आघात भी है। यही कारण है कि हॉलमार्किंग का मुद्दा केवल व्यापार का नहीं, बल्कि जनविश्वास का भी है।

कथित फर्जी हॉलमार्किंग के इस खेल से ईमानदारी से काम करने वाले कारोबारी भी प्रभावित होते हैं। जब कुछ लोग कम शुद्धता वाला सोना सैंदिग्ध हॉलमार्क के साथ बेचते हैं, तो ईमानदार ज्वेलरों के सामने गलत प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा होती है। कारोबारियों की

मांग है कि संबंधित दुकानों, आभूषणों, हॉलमार्किंग अभिलेखों और आपूर्ति श्रृंखला की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

भारतीय मानक ब्यूरो को हॉलमार्किंग केंद्रों और ज्वेलरों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कुछ कारोबारियों का आरोप है कि निगरानी और औचक जांच की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है तथा शिकायतों पर कार्रवाई में देरी होती है। यदि विभाग के पास मौखिक और लिखित शिकायतें पहले से हैं, तो

विपक्ष की नई करवट तीसरे मोर्चे की आहट

इंडिया ब्लॉक के भीतर बेचैनी क्यों

देश की विपक्षी राजनीति में एक बार

फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के सामने एक नई चुनौती उभरती दिख रही है। तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) अब कांग्रेस के साथ अपने पुराने रिश्तों को दोहराने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग राजनीतिक मंच की संभावनाएं तलाश रही है। यह घटनाक्रम केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश की विपक्षी एकजुता पर पड़ सकता है।

पिछले कुछ समय से डीएमके के सांसदों और नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जैसे दलों के नेताओं से मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि विपक्ष के भीतर एक समानांतर सोच पनप रही है। यह सोच भाजपा का विरोध तो करती है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पूरी तरह सहज नहीं है। डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में दारार की चर्चा के बाद से डीएमके तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश की विपक्षी एकजुता पर पड़ सकता है।

इसी पृष्ठभूमि में डीएमके ने केंद्र सरकार का विरोध जारी रखते हुए कांग्रेस से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यह केवल रणनीति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय राजनीति में केवल कनिष्ठ सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहते।

कांग्रेस के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती पैदा करती है। पहली चुनौती डीएमके की पहल है, जबकि दूसरी विपक्षी राजनीति में अपने नेतृत्व को स्वीकार्य बनाए रखने की है। यदि क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग साझा मंच बनाने लगते हैं, तो संसद में समन्वय, चुनावी गठबंधन और केंद्र सरकार का खिलाफ विपक्ष की एकजुता कमजोर हो सकती है। कांग्रेस को अपने सहयोगियों को साथ बनाए रखने के लिए अधिक लचीला होना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह एकजुता दिखाई है, वह अब धीरे-धीरे ढीली पड़ती दिख रही है। यदि डीएमके जैसा मजबूत दल अलग राह पकड़ता है, तो अन्य क्षेत्रीय दलों

उन पर त्वरित संज्ञान लिया जाना चाहिए। कार्रवाई में देरी से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के हौसले बढ़ सकते हैं। सरकार ने हॉलमार्किंग में पारदर्शिता लाने के लिए एचयूआईडी यानी हॉलमार्क यूनिफ आइडी की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत आभूषण पर छह अंकों का विशिष्ट कोड अंकित होता है, जिसके माध्यम से ग्राहक बीआईएस केयर एप पर उपलब्ध जानकारी की जांच कर सकता है। इससे आभूषण की पहचान, शुद्धता और हॉलमार्किंग से संबंधित विवरण जानने में मदद मिलती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए और ग्राहकों को सही जानकारी मिले। इसके लिए देशभर के हॉलमार्किंग केंद्रों और ज्वेलरी दुकानों की औचक जांच होनी चाहिए। सैंदिग्ध आभूषणों की प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाए और ग्राहकों को वैध हॉलमार्क तथा एचयूआईडी की पहचान करने के तरीके बताए जाएं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी की आशंका होने पर ग्राहक आसानी से शिकायत कर सकें और जो पर समयबद्ध कार्रवाई हो। ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के साथ फर्जीवाड़े में दोषी पाए जाने वालों के लाइसेंस रद्द करने और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की व्यवस्था भी प्रभावी होनी चाहिए। सोने का कारोबार केवल लाभ—हानि का कारोबार नहीं, बल्कि भरोसे का कारोबार है। यदि ग्राहक का भरोसा टूटता है, तो पूरा बाजार प्रभावित होता है। सोने की शुद्धता से खिलवाड़ केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला भी है। इसलिए हॉलमार्किंग से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच, पारदर्शी व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही ग्राहकों का भरोसा कायम रख सकती है।

(**नईदुनिया संपादकीय डेस्क**)

को भी नया विकल्प मिल सकता है।

तीसरे मोर्चे की चर्चा भारतीय राजनीति में नई नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे प्रयोग हुए हैं, लेकिन हर बार नेतृत्व, प्रधानमंत्री पद के चेहरे और भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति को लेकर सवाल उठे हैं। इस बार भी तीसरे मोर्चे के सामने वही चुनौतियां हैं। बीजेडी, आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल डीएमके के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को साथ लाना और लंबे समय तक एकजुट रखना आसान नहीं है। हर दल की अपनी महत्वाकांक्षा, जनाधार और राजस्तरिय मजबूरियां हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर साझा मंच बनाना और उसे प्रभावी ढंग से चलाना बड़ी चुनौती होगी। आज क्षेत्रीय दल केवल अपने राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे राष्ट्रीय नीतियों में भी अपनी भूमिका चाहते हैं। डीएमके की पहल इसी नई आकांक्षा का प्रतीक है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि गठबंधन में फैसले एकतरफा न हों, बल्कि सामूहिक सहमति से लिए जाएं और सभी की आवाज बराबरी से सुनी जाए।

विपक्ष में बिखराव का सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। यदि विपक्ष दो धड़ों में बंटता है, तो भाजपा विरोधी मतों के विभाजन से सत्तारूढ़ दल को फायदा हो सकता है। हालांकि, यदि तीसरा मोर्चा मजबूत होता है, तो वह उन राज्यों में भाजपा को चुनौती दे सकता है, जहां कांग्रेस कमजोर और क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। तमिलनाडु से करवट लेती राष्ट्रीय सियासत बताती है कि विपक्षी राजनीति एक नए मोड़ पर है। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का समय है। उसे सहयोगियों को भरोसा दिलाना होगा कि गठबंधन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है और नेतृत्व थोपा नहीं जाएगा, बल्कि साझा सहमति से तय होगा। वहीं, डीएमके जैसे दलों को भी विचार करना होगा कि अलग मंच बनाने से भाजपा के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी या विपक्ष और कमजोर होगी।

किसी भी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है। विपक्ष जितना एकजुट और रचनात्मक होगा, सरकार उतनी ही जवाबदेह बनेगी। तीसरे मोर्चे की चर्चा विपक्ष में नई सोच और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती आकांक्षाओं का संकेत है। आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां तय करेंगी की तीसरा मोर्चा केवल अटकल बनकर रह जाता है या वास्तव में एक नई राजनीतिक धारा के रूप में उभरता है।

(**नईदुनिया संपादकीय डेस्क**)

अपेक्षित बदलाव नहीं होता। जब

लोकतंत्र में संवाद की जगह टकराव लेने लगता है, तो असंतोष बढ़ता है। सोशल मीडिया ने इस आक्रोश को तेजी से फैलाने का काम किया है। एक शहर में हुई घटना दूसरे शहरों तक तुरंत पहुंच जाती है। गलत जानकारी और अफवाहों के कारण कई बार शांतिपूर्ण विरोध भी हिंसक रूप ले लेता है।

युवाओं की मांगें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और आवास जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ी हैं, लेकिन हिंसा और लूटपाट समाधान नहीं हैं। पेरिस में महंगे शोरूमों में लूटपाट से गरीबों का भला नहीं होगा, बल्कि इससे आंदोलन की विश्वसनीयता कमजोर होगी। हिंसा से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दूरी बढ़ती है तथा मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यूरोप में बढ़ता युवा असंतोष पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। सरकारों को युवाओं से संवाद करना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा

यूरोपीय देशों में क्यों भड़क रहे युवा

फ्रांस, इटली समेत कई देशों में आग

लेकर असुरक्षा और वर्तमान को लेकर

असंतोष। यूरोप में पिछले कुछ वर्षों में महंगाई बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद जीवनयापन की लागत में वृद्धि हुई है। घर का किराया, बिजली का बिल, खाने-पीने का खर्च और शिक्षा की फीस बढ़ी है, लेकिन वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। वे पढ़ाई पूरी करके नौकरी तलाशते हैं, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलने पर भी वेतन इतना कम होता है कि बड़े शहरों में जीवनयापन मुश्किल हो जाता है। जब दिन-रात मेहनत करने के बाद भी युवा अपने लिए छोटा-सा घर नहीं

खरीद पाता, तो व्यवस्था के प्रति उसके मन में गुस्सा पैदा होता है। यूरोप में शिक्षा को सामाजिक समानता का बड़ा माध्यम माना जाता रहा है, लेकिन अब उसी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ रही है और डिग्री हासिल करने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। जब शिक्षा, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद थी, बोझ बन जाए तो युवा खुद को ठग़ा हुआ महसूस करता है। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में आवास की कीमतें भी बड़ी समस्या बन गई हैं। बड़े शहरों में किराया इतना

अधिक है कि युवा अपनी आय का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च कर देते हैं। कई युवा तीस वर्ष की उम्र तक माता-पिता के साथ रहने को मजबूर हैं। इससे उनकी स्वतंत्र जीवन जीने और परिवार बनाने की योजनाएं प्रभावित होती हैं। जब रहने के लिए घर ही उपलब्ध न हो, तो व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। यूरोपीय युवाओं में राजनीतिक दलों और सरकारों के प्रति अविश्वास भी बढ़ा है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक राजनीतिक दल उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतियों में

और नीतियों में जरूरी बदलाव करने होंगे। आवास नीति में सुधार, सस्ती और रोजगारपरक शिक्षा तथा सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को भी युवाओं को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि नीति निर्माण में भागीदार समझना होगा। यूरोप की घटनाएं भारत के लिए भी सबक हैं। यहां भी युवा आबादी बहुत बड़ी है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ता आवास और सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा, तो असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए समय रहते युवाओं को वास्तविक अवसर उपलब्ध कराने होंगे। यूरोप की सड़कों पर दिखाई दे रही आग केवल दुकानों और इमारतों की आग नहीं, बल्कि युवाओं के भीतर सुलगते असंतोष का प्रतीक है। इस आग को संवाद, समाधान और संवेदना से ही **बुझाया जा सकता है।**

(**नईदुनिया संपादकीय डेस्क**)